सहमत मुक्तनाद

वर्ष:2 अंक:10-12 अक्टूबर-दिसंबर 2000

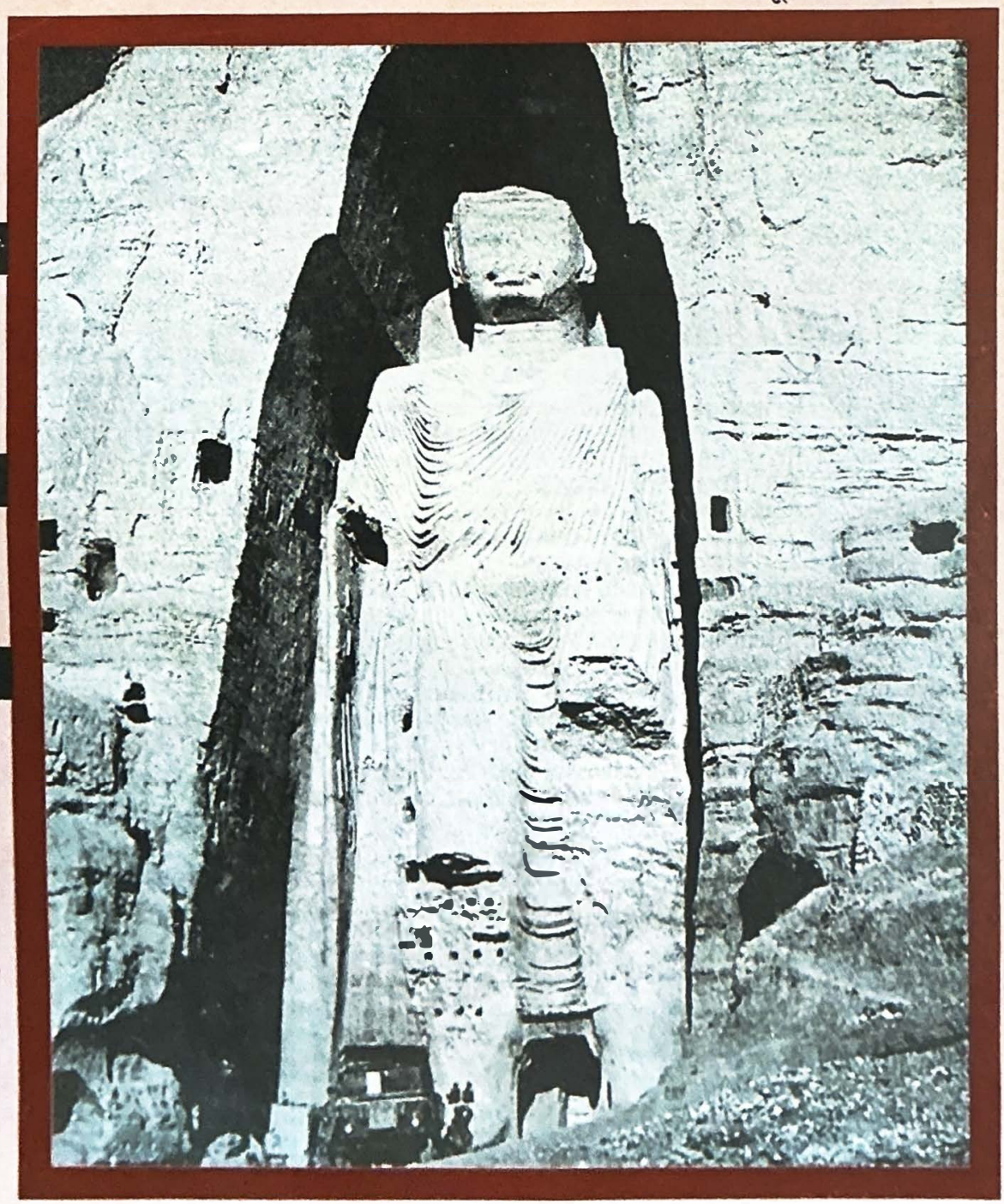

एलेन मिकसिन्स वुड

आधुनिकता, उत्तर-आधुनिकता या पूंजीवाद?

प्रभात पटनायक

सहस्त्राब्दी के आखिर में एशिया में पूंजीवाद

जयति घोष

पर्यावरण की रक्षा के सवाल और..

सहमत मुक्तनाद

वर्ष: 2 अंक : 10 - 12

अक्टबर - दिसंबर 2000

यह अंक - 25 रु.

वार्षिक सदस्यता - 150 रु.

संरक्षक मण्डल:

भीष्म साहनी

इरफान हबीब

सुवीरा जायसवाल

हबीब तनवीर

संपादक मण्डल:

के. एन. पणिक्कर

राजेन्द्र प्रसाद

अनिल चौधरी

राजेन्द्र शर्मा

शबनम हाशमी

संपादकीय व प्रबन्ध कार्यालय:

सहमत

8 विट्ठलभाई पटेल हाऊस

रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110 001

फोन 3711276, 3351424

आवरण चित्र: **बमियान बुद्ध:**
देखें पृष्ठ 80

अनुक्रम

1 **संपादकीय**
पाखंड और मुखौटे

4 **उत्सा पटनायक से बातचीत**
खेती की पैदावार के बाजार खोलने का रास्ता हमारे जैसे देशों के लिए तबाही का रास्ता है

8 **एम एस स्वामीनाथन**
पश्चिम के पक्ष में झुकी हुई हैं विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्थाएं

10 **के टी रवींद्रन**
गरीबों की घेराबंदी

13 **जयति घोष**
चिंता प्रदूषण की: पर नागरिकों के अधिकार?

185 **एजाज अहमद**
आखिर यह किस का समाज है?

20 **अशोक मित्र**
कलकत्ता डायरी

23 **सुकुमार मुरलीधरन**
जनतंत्र के पक्ष में राष्ट्रपति का हस्तक्षेप

26 **श्रीकांत मिश्र**
बहुराष्ट्रीय कंपनियां: गुलामी का मंत्र

29 **एलेन मिकसिन्स वुड**
आधुनिकता, उत्तर-आधुनिकता या पूंजीवाद?

29 **सुहैल हाश्मी**
मुस्लिम वोट बैंक का सवाल

39 **विष्णु नागर**
प्रधानमंत्री के आपरेशन के बहाने

44 **भूपेंद्र यादव**
साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं

46 **जवरीमल्ल पारख**
'संवाद' के जरिए नफरत का अभियान

50 **प्रभात पटनायक**
सहस्राब्दी के आखिर में एशिया में पूंजीवाद

60 **रोनाल्ड एच हैरिंग**
जहां वोट काम न आए

64 **विजय प्रसाद**
अमरीका: राष्ट्रपति चुनाव और बुश द्वितीय का राज्यारोहण

68 **रामसुजान अमर**
शिक्षा से खिलवाड़ जारी है

71 **राजेंद्र शर्मा**
महिला आरक्षण पर भाजपा की पलटी यानी एक और पाखंड का अंत

74

77 **भगवान प्रसाद** सिन्हा
सचमुच सरदार

80 **बमियान बुद्ध:**
सहमत द्वारा आयोजित विरोध

संपादन और प्रकाशन पूर्णतः अवैतनिक
टिप्पणियों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं
जिनसे संपादक/प्रकाशक का सहमत होना
जरूरी नहीं है।

सारा भुगतान चैक या बैंक ड्राफ्ट से सहमत
के नाम से किए जाएं।

विज्ञापन की दरें

बैक कवर	5,000 रु
भीतर का कवर	4,000 रु.
पूरा पेज	2,000 रु.
आधा पेज	1,000 रु

संपादकीय

पाखंड और मुखौटे

अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के सिर्फ नौ वर्ष बाद, इस कांड की जांच करने के लिए नियुक्त जस्टिस लिबरहाल आयोग के सामने अपनी गवाही में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक के एस सुदर्शन ने आखिरकार, बाकायदा यह दावा पेश कर दिया कि इस प्रकरण से आर एस एस तथा उसके बाजुओं का कोई लेना-देना नहीं था। अगर इस पैंतरे के निहितार्थ इतने खतरनाक न होते तो, "वहीं" मंदिर बनाने को आस्था का सवाल बताने तथा उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होने का दम भरने वालों की इस दयनीय परिणति पर, अगर हमें तरस न भी आता तब भी हंस तो सकते ही थे। सुदर्शन का कहना था कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरायी जरूर गयी थी और उस समय आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी तथा उमा भारती समेत अनेक प्रमुख भाजपा नेता तथा संघ परिवार के अन्य बाजुओं के अनेक प्रमुख नेता वहां मौजूद भी थे, इसके बावजूद उन पर किसी भी तरह बाबरी मस्जिद के गिराए जाने की जिम्मेदारी नहीं आती है। उन्होंने विशेष रूप से इस समय केंद्र सरकार में मंत्रिपद पर बैठे आडवाणी, जोशी तथा उमा भारती के संबंध में यह दावा किया कि मस्जिद गिराने में कोई हाथ होना तो दूर, वे तो वास्तव में "कार सेवकों" को नियंत्रित करने, उन्हें मस्जिद को कोई नुकसान न पहुंचाने के लिए मानने की ही कोशिश कर रहे थे। बेशक, आर एस एस के सरसंघचालक का एक न्यायिक आयोग के सामने शपथपूर्वक दिया गया यह बयान इस दृष्टि से आश्चर्यजनक भी नहीं था कि उनके, विशेष रूप से केंद्र में सरकार में बैठे भाजपा नेताओं का ऐसा ही कोई बचाव पेश करने के संकेत पहले ही आ चुके थे।

वास्तव में, आर एस एस के प्रमुख इससे पहले, सम्मानित गांधीवादी समाजसेविका निर्मला देशपांडे के एक साक्षात्कार के हवाले से, इससे भी हास्यास्पद दावा पेश कर चुके थे कि मस्जिद बम से गिरायी गयी थी, यह काम किन्हीं विशेषज्ञों का था, इसके पीछे कोई गहरा षडयंत्र रहा हो सकता है और इस षडयंत्र के सूत्र एक ओर तत्कालीन केंद्र सरकार तक और दूसरी ओर किसी अज्ञातनामा मुस्लिम ग्रुप तक जाते नजर आते हैं। निर्मला देशपांडे के जोर-शोर से, यहां तक कि खुद लिबरहाल आयोग के सामने इन दावों का खंडन करने तथा इससे भी आगे बढ़कर यह स्पष्ट करने के बाद कि उनका आशय आर एस एस जैसे संगठन द्वारा सोच-समझ कर तथा पूरी तैयारी के साथ मस्जिद ढहाये जाने से था, आर एस एस के सरसंघचालक को अपना बयान बदलना पड़ा था। बहरहाल, सुदर्शन ने अपना बयान जरूर बदला लेकिन, इस बयान के पीछे छिपी अपनी कार्यनीति जरा भी नहीं बदली। स्वाभाविक रूप से उनका नया बयान भी, मस्जिद ढहाने की जिम्मेदारी से विशेष रूप से आडवाणी-जोशी-उमा की तिकड़ी तथा आम तौर पर संघ परिवार को, मुक्त करने की ही कोशिश करता है। याद रहे कि इससे पहले, केंद्रीय मंत्रिमंडल की इस अयोध्या तिकड़ी में से कनिष्ठतम, उमा भारती खुद भी लिबरहाल आयोग के सामने अपनी गवाही में, यह दावा पेश कर चुकी थीं कि मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचाना तो दूर, उन्होंने तो वास्तव में कार सेवकों से मस्जिद को बचाने की ही कोशिश की थी। लेकिन, उन लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी। जाहिर है कि आयोग के सामने जिरह में उन्हें अनेक साक्ष्यों के सामने बार-बार इस जाने-पहचाने बहाने का आश्रय लेना पड़ा था कि अब इतने अर्से बाद, उन्हें कुछ याद नहीं पड़ रहा है।

और जैसे कि सब कुछ पहले से ही तय था, इस बार ६ दिसंबर के गिर्द आडवाणी-जोशी-उमा तिकड़ी के मस्जिद गिराने के कांड में लिप्त होने के लिए इस्तीफे मांगे जाने पर, उनके बचाव में वाजपेयी ने संभवत: पहली बार अपनी तरफ से यह दावा पेश किया कि उक्त नेतागण तो, मस्जिद को गिराने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए अयोध्या गए थे। तो क्या जनाब वाजपेयी ही मस्जिद को गिरते देखना चाहते थे, जो अपने साथियों के साथ मस्जिद बचाने के लिए अयोध्या तक न जाकर, लखनऊ में ही रुके रहे थे! वास्तव में इस सबकी पृष्ठभूमि में इसे सिर्फ संयोग मानने पर संदेह उठने स्वाभाविक हैं कि आम तौर पर संघ परिवार तथा खासतौर पर भाजपा नेताओं को मस्जिद गिराने के लिए हर तरह की जिम्मेदारी से अलग करने के इन सुव्यवस्थित दावों के कुछ ही अर्से में, आडवाणी-जोशी-उमा समेत संघ परिवार के आठ प्रमुख बाबरी वीरों के खिलाफ षडयंत्र का मामला विशेष अदालत को सोंपे जाने का सरकार का 1993 का निर्णय, शुद्ध तकनीकी आधार पर निरस्त कर दिया जाता है। और इसके बाद शुरू हो जाता है इसके झूठे दावों का सिलसिला कि अब तो अदालत ने भी मान लिया कि आडवाणी आदि मस्जिद के मामले में बेकसूर हैं और उन्हें तो राजनीतिक कारणों से झूठ-मूठ इस मामले में फसाया गया था! यानी सारी कोशिश इसकी है कि आठ वर्ष से कुछ पहले, 6 दिसंबर को अयोध्या में भीड़ जुटाकर मस्जिद को ढहाने की जो जघन्यता की गयी थी, उसकी जिम्मेदारी से इस अभियान के नेताओं को बचाया जाए।

बेशक, इस नंगईभरी कोशिश पर तो हैरानी से किसी का दम तक निकल सकता है। आखिर, मुश्किल से सिर्फ आठ साल पहले और अयोध्या में जुटाए गए लाख से ज्यादा लोगों के ही नहीं, टेलीविजन के जरिए देश भर में तथा दुनिया भर में लोगों के देखते-देखते, उस काले रविवार को अयोध्या में तथा उसकी तैयारी में देश भर में कोई दो वर्ष से जो कुछ हो रहा था, उससे इस तरह सिरे से ही इंकार करने की कोशिश कोई कैसे कर सकता है? क्या कथित कार सेवा के लिए लाखों लोगों को जुटाने के लिए संघ परिवार द्वारा तथा भाजपा की राज्य सरकारों द्वारा किए गए सारे प्रबंधों के अलावा आडवाणी, जोशी आदि ने नवंबर के आखिरी तथा दिसंबर